राज्य सरकार को 3 करोड़ रुपये की राशि रिलीज की गई थी। बाद में राज्य सरकार ने आबंटित राशि में ही साबरकंठा जिले में 339 हैंडपम्प लगाए जाने वाली 229 बस्तियों और बनासकंठा जिले में 82 हैंडपम्प लगाए जाने वाली 62 बस्तियों को शामिल कर लिया था।

(ग) उपरोक्त योजना के अंतर्गत जनवरी, 1993 तक लगाए गए हैंडपम्पों की संख्या के जिला-वार ब्यौरे निम्नलिखित हैं :–

क्रमांक	जिले का नाम	लगाए गए हैंडपम्पों की संख्या
1.	बड़ौदरा	70
2.	पंचमहल	190
3.	सूरत	40
4.	भड़ौच	61
5.	बलसाड़	304
6.	साबरकंठा	153
7.	बनासकंठा	37
	योग :	855

Shortage of Vitamin 'C'

236. SHRI MOHD. KHALEELUR RAHMAN: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that there is a chronic and continuing shortage of Vitamin 'C' formulations and multi vitamin preparations containing vitamin 'C' for the last several months;

(b) if so, what are the reasons therefor;

(c) whether Government propose to allow import of Vitamin 'C' at concessional rate of custom duty;

(d) if not, the reasons therefor; and

(e) what other steps Government proopse to take in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI EDUARDO FALEIRO): (a) and (b) Supply of bulk Vitamin C had got dislocated during the second and third quarters of 1992 due to shortfall in production of one of the two units. The position has since improved and, as per the available information, the present production level is adequate to meet the estimated demand.

(c) to (e) At present there is no proposal to reduce the customs duty on Vitamin C. Government, however, is keeping a constant watch and in case the situation so warrants, duty reduction would be considered in the consumer interest.

Development of a substitute for timber

SHRI MOHAMMED SALIM: SHRI M. A. BABY:

Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to a meet on developing substitutes for timber was held recently in the Capital;

(b) whether efforts to develop a substitute for timber as industrial and construction sector material would get adequate support; and

(c) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (DEPARMENT OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT) WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (DEPARTMENT OF HEAVY INDUSTRY) (SHRIMATI KRISHNA SAHI): (a) Yes, Sir.

(b) and (c) The Policy Advisory Group on Wood Substitution of the

Ministry of Environment and Forests has, inter-alia, recommended encouraging the development and use of returnable plastic trays, card board boxes, corrugated fibre board boxes, multiwalled craft paper racks and polythene laminated jute boxes for packing, replacement of wooden sleepers by concrete sleepers, encouraging panels manufactured out of non-wood material like bagasse, rice husk, jute, etc., shifting from the use of timber to steel in construction and furniture, and exemption in excise duty on plastic, steel and aluminium furniture.

पूंजी निवेश

*238. **श्री सोमपाल** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई आर्थिक नीति के फलस्वरूप, किन किन क्षेत्रों में पूंजी निवेश किया गया है और इसका किन किन राज्यों को लाभ मिला है;

(ख) क्या यह सच है कि उक्त पूंजी निवेश का लाभ पिछड़े राज्यों तक नहीं पहुंच पाया है; और

(ग) यदि हां, तो पिछड़े क्षेत्रों में अधिक अधिक उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार की क्या योजना है ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) में राज्य मंत्री तथा उद्योग मंत्रालय (भारी उद्योग विभाग में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) लाइसेंस-मुक्त उद्योगों के लिये औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन मुख्यत: धातुकर्मी, खाद्य प्रसंस्करण, रसायन, वस्त्र और विद्युत मशीनरी क्षेत्रों के लिये प्रस्तुत किये गये हैं। लाइसेंस प्राप्त उद्योगों के लिये आशय-पत्र मुख्यत: औषधि और भेषज, फर्मेंटेशन उद्योग, रसायन उद्योग आदि के लिये मंजूर किये गये हैं। निवेश करने की इच्छा रखने वाले राज्यों में महाराष्ट्र, गुजरात और उत्तर प्रदेश प्रमुख हैं।

(ख) और (ग) जी, नहीं। 38 प्रतिशत से अधिक औद्योगिक उद्यम ज्ञापन और 48 प्रतिशत से अधिक आशय-पत्र औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े जिलों के लिये दिये गये हैं।

1993-94 के बजट में पूर्वोत्तर राज्यों, जम्मू तथा कश्मीर, हिमाचल प्रदेश सिक्किम, गोवा और संघ शासित क्षेत्र अंडमान एवं निकोबार, दादरा एवं नगर हवेली, दमन एवं दीव, लक्षदीप और पांडिचेरी में नये औद्योगिक उपक्रमों के लिये पांच वर्ष के करावकाश का प्रस्ताव है जो उत्पादन के वर्ष से शुरू होगा।

Additional outlay for the minimum needs programme

*239. MISS SAROJ KHAPARDE: Will the Minister of PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION be pleased to state:

(a) whether it is a fact that an additional outlay of Rs. 500 crores has been made in the Eighth Plan for a new component of the Minimum Needs Programme for Rural Domestic Energy incorporated into the Integrated Rural Energy Programme (IREP); and

(b) if so, what are the details thereof?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION (SHRI GIRIDHAR GOMANGO): (a) and (b) A provision of Rs. 500.00 crores has been made in the Eighth Plan for the Minimum Domestic Energy Needs of the economically weaker sections in the blocks covered under the Integrated Rural Energy Programme. The Programme details and its funding arrangements are benig worked out.

जवाहर रोजगार योजना के अधीन राजस्थान को केन्द्रीय सहायता

*240. **श्री मूल चन्द मीणा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जवाहर रोजगार योजना के अधीन, केन्द्रीय सरकार से राजस्थान